



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर)



क्रमांक:-एफ -5() के.स्टोर/सा.प्र./ननिज/ग्रेटर/2022-23दिनांक:-

A. बोली की शर्तें एवं नियम


बोलीदाता को बोली बोली में अपनी दरें अंकित करते समय इन शर्तों को बहुत सावधानी पूर्व पढ़ लेना चाहिए।

1. बोली किसको संबोधित की जानी है :-उपायुक्त(स्टोर) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. बोलीदाता का जी.एस.टी. एक्ट के तहत पंजीयन होना अनिवार्य है। जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति तकनीकी बिड के साथ संलग्न करनी होगी। GST Registration के अभाव में बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. दरें गन्तव्य स्थान (सेन्ट्रल स्टोर नगर निगम ग्रेटर जयपुर) तक एफ.ओ.आर अंकित की जानी चाहिए। प्रस्तुत दरों में विषयवस्तु की लागत के साथ सभी आनुषांगिक प्रभारों को शामिल किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की दर देयता की स्थिति में उसके भुगतान का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।
4. सशर्त बोली मान्य नहीं की जायेगी।
5. तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाली सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से मांग के अनुसार होना चाहिए। किसी प्रकार से अपूर्ण दस्तावेज होने पर उस बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. न्यूनतम दरे स्वीकार करने के लिए कय/उपापन समिति बाध्य नहीं है। सर्वाधिक लाभप्रद बोली के साथ-साथ सामग्री का मैक/क्वालिटी/पूर्व अनुभव व बोलीदाता के पास उपलब्ध संसाधन आदि के आधार को ध्यान में रखा जावेगा।
7. सफल बोलीदाता को बोली की अनुमानित लागत का 2.5 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रूप में डी. डी. अथवा बैंकर चैक के माध्यम से जमा करानी होगी। सफल बोलीदाता को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा। स्टाम्प का व्यय बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा। बोली प्रतिभूति राशि इसमें समायोजनीय होगी। निम्न स्थितियों के कार्य सम्पादन प्रतिभूति को जब्त किया जा सकता है -
 - (क) जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - (ख) जबबोलीदाता संपूर्ण प्रदाय संतोष जनक ढंग से करने में असफल रहा हो
 - (ग) प्रतिभूति निक्षेप (एस.डी) को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।
8. बोली में सामग्री की सम्भावित मात्रा/संख्या दर्शायी गई है। इस मात्रा को तात्कालिक आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जा सकता है।
9. अनुमोदित दरें 1 वर्ष तक की अवधि के लिए मान्य होगी। जो कि सर्वसहमती से बढ़ाई जा सकती है।
10. सम्पूर्ण बोली या उसके किसी भाग को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर को होगा। आवश्यकतानुसार कोई अन्य शर्त बोलीदाता को मान्य होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

11. निम्नस्थिति में बोलीदाता बोली में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा।
(क) यदि उसे राज्य सरकार, किसी सरकारी संस्था या उपापन संस्था द्वारा गत तीन वर्षों में ब्लैक लिस्टेड किया गया हो।
- बोलीदाता को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी भी उपापन संस्था द्वारा वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया हुआ है। यदि बोलीदाता द्वारा अपनी अर्हता के संबंध में प्रस्तुत सूचना /दस्तावेज असत्य या दुर्व्यपदेशन गठित करने वाली अथवा सारावन रूप से गलत या अपूर्ण पायी जाती है, तो बोलीदाता के साथ की गई संविदा को निरस्त करते हुए जमा बोली प्रतिभूति राशि को जब्त किया जा सकेगा।
12. बोली दाताओं को बोली प्रपत्र शुल्क, बोली धरोहर राशि, एवं ई-बोली प्रोसेसिंग फीस ऑन लाईन नगर निगम, ग्रेटर जयपुर की वेबसाइट www.jaipurmc.org.com पर Submission end Date of Time से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को स्केन करके www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने पर ही बोली को मान्य किया जायेगा। उक्त जमा राशि की प्राप्त रसीद की प्रतिलिपी तकनिकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अभाव में बोली प्रस्ताव अमान्य माना जावेगा।
13. बोलीदाता को आयुक्त, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर के पक्ष में Bid Security (EMD) 2 प्रतिशत प्रस्तुत करनी होगी।
14. बोली प्रतिभूति राशि का निम्न परिस्थितियों में समपहरण किया जा सकेगा।
- जब बोली दाता बोली खोले जाने के पश्चात किन्तु बोली की स्वीकृति से पूर्व बोली वापिस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
 - जब बोली दाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार, यदि कोई हो, सम्पादित नहीं करता।
 - जब प्रदाय आदेश दिये जाने के पश्चात बोलीदाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता।
 - जबवह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में विफल रहता है।
15. सफल बोलीदाता अपनेकार्य/संविदा को अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/एजेन्सी को नहीं सौपेगा या सब-लेट नहीं करेगा।
16. बोलीदाता बोली में अपना/अपनी ओर से अधिकृत व्यक्ति का पूर्ण पता एवं टेलीफोन/मोबाइल नम्बर अंकित करेगा।
17. देय भुगतान में से नियमानुसार स्रोत पर आयकर (TDS), जी.एस.टी. एक्ट के तहत TDS कटौती की जावेगी।
18. बोली प्रपत्रों की शर्तों, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम 2013 में उल्लेखित नियम उपापन संस्था एवं बोलीदाता दोनों को मान्य होंगे।
19. स्वीकृत बोलीदाता को सामग्री/सेवाओं की व्यवस्था उपापन संस्था की आवश्यकतानुसार (संबंधित प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार) अविलम्ब करनी होगी। आवश्यक समझे जाने पर बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवायी जाने वाली सामग्री/सेवाओं की जांच की जा सकेगी। संबंधित प्रभारी अधिकारी प्रमाणीकरण के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
20. क्रय आदेश दिए जाने की दिनांक से 03 दिवस अथवा (क्रय आदेश में उल्लेखित अवधि) के भीतर फर्म द्वारा माल की पूर्ण आपूर्ति केन्द्रीय स्टोर, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर में की जायेगी तथा विलम्ब की स्थिति में नियमानुसार शास्ति अधिरोपित की जावेगी।


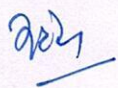
बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर



21. समस्त प्रस्तावित दरे एफ.ओ.आर. केन्द्रीय स्टोर, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर की होनी चाहिए और उनमें समस्त कर शामिल होने चाहिए अथवा कर के संबंध में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। स्थानीय प्रदाय के मामलों में व दरों में समस्त कर शामिल होने चाहिए। संविदा का मूल्यांकन कर दायित्व सहित किया जायेगा एवं अनुमोदित दर के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी।
22. बोलीदाता को बोली में अंकित अवधि में खेल सामग्री/उपकरण की आपूर्ति करनी होगी। अन्यथा विलम्ब से आपूर्ति करने पर निम्नानुसार परिसमापित नुकसानी (Liquidated Damage)की कटौती की जायेगी।

क- विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि का विलम्ब	2.5 प्रतिशत
ख- विहित कालावधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधे से अधिक कालावधि का विलम्ब	5 प्रतिशत
ग- विहित कालावधि से आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई तक की कालावधि का विलम्ब	7.5 प्रतिशत
घ- विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कालावधि का विलम्ब	10 प्रतिशत
23. प्रदाय में विलम्ब की गणना करते समय दिन के भाग की अवेहलना कर दी जावेगी। यदि वह आधे दिन से कम है।
24. निर्धारित नुकसान की अधिकतम रकम 10 प्रतिशत होगी।
25. बोली में दी गयी कालावधि के दौरान अपेक्षित माल की अनुमानित मात्रा बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस में उपदर्शित की गई है। किन्तु इनकी न्यूनतम मात्रा की कोई गारण्टी नहीं है।
26. यदि माल/सेवा के प्रदाय में विलम्ब बोलीदाता के नियंत्रण से परे बाधाओं के कारण हो एवं प्रदाय की पूर्ति में प्रदायक समय की वृद्धि चाहता है तो सक्षम प्राधिकारी को बाधा के गठित/उत्पन्न होते ही उसके लिए लिखित में तुरन्त आवेदन करेगा। इस पर निर्णय आयुक्त, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर द्वारा किया जायेगा जो अंतिम होगा।
27. प्रदाय की गई समस्त वस्तुएं बोली प्रारूप में अभिकथित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के अनुरूप होगी तथा कई वस्तुएं आई.एस.आई./आई.एस.ओ./एगमार्क आदि विनिर्देशों के अनुरूप होना अपेक्षित हो, तो वे वस्तुएं उन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप होगी और उन पर ऐसा मार्क होना ही चाहिए।
28. बोलीदाता द्वारा प्रदाय किया गया माल बोली में वर्णित विवरण और क्वालिटी के अनुरूप नहीं पाया जाने की स्थिति में उपायुक्त स्टोर, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर को सुपुर्दगी अस्वीकृत करने हेतु अधिकृत होगा। जिस पर बोलीदाता को वांछित क्वालिटी का माल प्रदाय करना होगा।
29. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 10 दिवस के अन्दर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। बिल का भुगतान निगम कोष में सम्बन्धित विभाग से फण्ड प्राप्त होने पर अथवा बिल पारित होने पर किया जावेगा। विलम्ब के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
30. विलम्ब से प्राप्त होने वाली बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा। विलम्ब के लिए बोलीदाता स्वयं ही जिम्मेदार होगा। यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
31. बोलीदाताको किसी शर्त के संबंध में संशय होने पर बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से पूर्व तक कार्यालय में किसी कार्य दिवस में संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
32. सप्लाई आदेश जारी होने के बाद निर्धारित अवधि/समय में खेल सामग्री/उपकरण इस कार्यालय की भण्डार शाखा अथवा निर्दिष्ट स्थान पर बोलीदाता को स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध करानी होगी। निर्धारित अवधि में निर्देशित खेल सामग्री/उपकरण की अपूर्ति अपेक्षित मात्रा एवं क्वालिटी की नहीं होने की स्थिति में बोलीदाता की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर अन्य फर्म से कार्य करवाया जा सकेगा। साथ ही दोषी फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

33. परिसम्पत्ति नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट, रदद की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट रदद किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अर्न्तगत कार्रवाही की जाएगी।
34. किसी बिन्दु पर आपसी असहमति होने पर आयुक्त, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर का निर्णय सर्वमान्य होगा। यदि न्यायिक वाद संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, न्यायिक वाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
35. प्रथम अपील अधिकारी निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर एवं द्वितीय अपील अधिकारी शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर होगा।
36. बोली में जिस मेक, साईज, उत्पादन आदि का माल/सामग्री चाही गई है उसी दर एवं स्पेशीफिकेशन अनुसार आपूर्ति करनी होगी।
37. उक्त सभी आईटम के सेम्पल प्रस्तुत करना होगा।
- उपरोक्त शर्तें संख्या 01 से 37 तक को मेरे द्वारा ध्यान पूर्वक पढ लिया गया है तथा मुझे सभी शर्तें पूर्णतया स्वीकार है जिसे हस्ताक्षर सहित उक्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर पुनः प्रस्तुत है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर



B. खेल सामग्री/उपकरण क्रय किये जाने हेतु प्रस्तुत दर संविदा हेतु "तकनीकी प्रस्ताव प्रारूप"

नगर निगम, ग्रेटर जयपुर द्वारा राजीव गाँधी शहरी ओलम्पिक खेल 2022-23 के अर्न्तगत आयोजित खेल हेतु खेल उपकरण/सामग्री क्रय कार्य हेतु बोलीदाता की आवश्यक तकनीकी योग्यताएँ :-

क्र. सं.	आवश्यक योग्यताएँ	वांछित प्रपत्र
01.	बोलीदाता का नाम, पता, मोबाईल नं० ई-मेल का पूर्ण विवरण	बोलीदाता को संस्था के लेटर हैड पर पूर्ण विवरण अंकित कर हस्ताक्षर कर संलग्न करना है।
02.	बोली दस्तावेज शुल्क राशि 200/- जमा कराने की रसीद की प्रतिलिपी	नगर निगम, ग्रेटर जयपुर की हैल्पलाईन पर बोली दस्तावेज शुल्क राशि की रसीद की प्रतिलिपी संलग्न कर।
03.	बोली धरोहर राशि 6800/- जमा कराने की रसीद की प्रतिलिपी।	नगर निगम, ग्रेटर जयपुर की हैल्पलाईन पर बोली दस्तावेज शुल्क राशि की रसीद की प्रतिलिपी संलग्न कर बोली धरोहर राशि।
04.	बोलीदाता को किसी विभाग बोर्ड कॉर्पोरेशन/प्राधिकरण/सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय द्वारा बोली की दिनांक से गत 3 वर्षों में अयोग्य/ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं होना चाहिए।	बोलीदाता को राशि 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अयोग्य/ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं करने का स्वप्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करना होगा।
05.	बोलीदाता फर्म/साझेदार/कम्पनी एवं GST No. प्राप्त किया गया हो एवं बोलीदाता फर्म के विरुद्ध GST बकाया नहीं होना चाहिए।	GST रजिस्ट्रेशन पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी है एवं Latest Month GST RETURN की प्रति संलग्न करें।
06.	बोलीदाता को किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निगम/बोर्ड/ऑथोरिटी में गत 5 वर्षों (वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22) में से कम से कम 03 वर्षों में सामान सम्पलाई का कार्यानुभव होना आवश्यक है।	बोलीदाता को निर्धारित वर्षों में से 03 वर्षों के कार्यादेश/अनुभव प्रमाण-पत्र/संतोषजनक कार्य का प्रमाण-पत्र संलग्न करने होंगे।
07.	बोलीदाता को पेन कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।	बोलीदाता को पेन कार्ड की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी है।
08.	बोली आमंत्रण सूचना के साथ संलग्न निविदा शर्तों एवं Annexure A, B, D को बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित कर संलग्न करें।	बोली निविदा शर्तों एवं Annexure A, B, D को बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित कर संलग्न करें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम

पता

मो० नं०

ई-मेल



C. खेल सामग्री/उपकरण सप्लाई/कय करने हेतु दर संविदा हेतु "वित्तीय प्रस्ताव प्रारूप"

नगर निगम, ग्रेटर जयपुर द्वारा राजीव गाँधी शहरी ओलम्पिक खेल 2022-23 के अर्न्तगत आयोजित खेल हेतु खेल उपकरण/सामग्री कय कार्य हेतु बोलीदाता की आवश्यक तकनीकी योग्यताएँ :-

क्र. सं.	खेल सामग्री/उपकरण अथवा आईटम का नाम	स्पेशिफिकेशन कम्पनी/ब्राण्ड	मात्रा	इकाई	प्रस्तुत बोली दर मय समस्त कर एवं एफ.ओ.आर.
01.	बॉलीवाल बॉल	NIVIA/COSCO/MIKASA (अच्छी क्वालिटी)	68	Per PC	
02.	नेट बॉलीबाल (कॉटन)	NIVIA/ K.K./ SAGAR (अच्छी क्वालिटी)	34	Per PC	
03.	फुटबॉल	NIVIA/COSCO (अच्छी क्वालिटी)	68	Per PC	
04.	फुटबॉल नेट (नायलॉन)	NIVIA/ K.K./ SAGAR (अच्छी क्वालिटी)	68	Per PC	
05.	बॉस्केटबॉल (पुरुष) 7 नम्बर	NIVIA/COSCO/ADIDAS (अच्छी क्वालिटी)	34	Per PC	
06.	बॉस्केटबॉल (महिला) 6 नम्बर	NIVIA/COSCO/ADIDAS (अच्छी क्वालिटी)	34	Per PC	
07.	बास्केटबॉल नेट (कलर मे)	NIVIA/COSCO/ADIDAS (अच्छी क्वालिटी)	68	Per PC	
08.	व्यक्तिगत फाउल इंडिकेटर (1+5)	(अच्छी क्वालिटी)	34	Per PC	
09.	झण्डी कपडे में 1.5'X1.5'	(अच्छी क्वालिटी)	34	Per PC	
10.	क्रिकेट बेट (टेनिस बॉल हेतु)	SS, SG, SF	68	Per PC	
11.	टेनिसबॉल क्रिकेट (बॉल)	NIVIA/ COSCO	400	Per PC	
12.	स्टम्प(3 नग सेट बेल्स सहित)	NIVIA/ COSCO	68	Per Set	
13.	एल गार्ड	NIVIA/ COSCO	105	Per PC	
14.	बिशिल	FOX FOURTY	350	Per PC	
15.	स्टॉप वॉच	NIVIA RECER	105	Per PC	
16.	फिता (मेजरमेन्ट के लिए)	(आई.एस.आई मार्का) 100 मीटर	34	Per PC	
17.	क्लीपर	(आई.एस.आई मार्का)	34	Per PC	
18.	स्कोरशीट (01 खेल)	MI COMPANY	आवश्यकता अनुसार	Per Sheet	
19.	रस्सी (कॉटन)	40 मीटर के स्पाईन के अलग-अलग बंडल	1360 मीटर	Per PC	


बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम

पता

मो0 नं0

ई-मेल

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....

 (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....

Place

Date

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Annexure E

Clause 1: Fair Wage Clause

- (a) The Contractor shall pay not less than fair wages/minimum wages to labours engaged by him on the work as revised from time to time by the Government, but the Government shall not be liable to pay any thing extra for it except as stipulated in price escalation clause (clause 45) of the agreement.

Explanation: "Fair Wage" means minimum wages for time or piece work, fixed revised, by the State Government under the Minimum Wages Act, 1948.

- (b) The Contractor shall, notwithstanding the provision of any contract to the contrary, cause to be paid fair wages to labourers indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-contractors in connection with the said work as if the labourers have been immediately or directly employed by him.
- (c) In respect of all labourers, immediately or directly employed on the work, for the purpose of the Contractor's part of this agreement, the Contractor shall comply with or cause to be complied with the Public Works Department Contractor's Labour Regulations made, or that may be made by the Government, from time to time, in regard to payment of wages, wage period, deductions from wages, recovery of wages not paid, and unauthorised deductions, maintenance of wages register, wage card, publication of scale of wages and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and other matters of a like nature.
- (d) The Engineer-in-charge shall have the right to deduct from the money due to the Contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers, by reasons of non-fulfilment of the conditions of the contract, for the benefit of the worker or workers, non-payment of wages or of deductions made there from, which are not justified by the terms of the contract, or as a result of non-observance of the aforesaid regulations.
- (e) Vis-à-Vis the Municipal Corporation Jaipur, the Contractor shall be primarily liable for all payments to be made and for the observance of the regulations aforesaid, without prejudice to his right to claim indemnity from his subcontractors,
- (f) The regulations, aforesaid, shall be deemed to be part of this contract and any breach, thereof, shall be breach of the contract.

Clause 2: Contractor to engage technical staff

The Contractor shall engage the technical staff, as follows, on the contract works:-

- (a) For works costing Rs. 100 lac and above- One Graduate Engineer.
- (b) For works costing between Rs. 50 lac to Rs. 100 lac- One qualified diploma holder having experience of not less than 3 years.
- (c) For works costing between Rs. 15 lac and Rs. 50 lac- One qualified diploma holder.

The technical staff should be available at site, whenever required by Engineer-in-charge to take instructions.

Clause 3 :

The Contractor shall comply with the provisions of the Apprenticeship Act, 1961, and the Rules and Orders issued, there under, from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of contract. The Contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the said Act.

Clause 4: Safety Code

The Contractor shall follow the safety code of electricity Strictly.

Clause 5:

Near Relatives barred from tendering

The Contractor shall not be permitted to tender for works in Circle, in which his near relative is posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of the Superintending Engineer and Assistant Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons, who are working with him in any capacity, or are subsequently employed by him and who are near relatives to any gazetted officer in the Organization/Department. Any breach of this condition by the Contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of the Department. If such facts are noticed (a) before sanction of tender, his offer shall be declared invalid and earnest money shall be forfeited, (b) after sanction of the tender then the tender sanctioning authority may at his discretion forfeit his earnest money, performance guarantee, security deposit and enlistment deposit and the work/remaining work may allot to any registered contractor on the same rates as per rules.

Note: By the term 'near relative' is meant wife, husband, parents and grand-parents, children and grand children, brothers and sisters, uncles and cousins and their corresponding in-laws.

Clause 6: Retired Gazetted Officers barred for 2 years

No Engineer of Gazetted rank or other Gazetted Officer, employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Government of Rajasthan, is allowed to work as a Contractor for a period of 2 years of his retirement from Government service without the previous permission of Government of Rajasthan. The contract is liable to be cancelled, if either the Contractor or any of his employees is found, at any time, to be such a person, who had not obtained the permission of Government, as aforesaid, before, submission of the tender or engagement in the contractor's service, as the case may be.

Clause 7: Quality Control

The Municipal Corporation Jaipur shall have right to exercise proper Quality Control measures. The Contractor shall provide all assistance to conduct such tests and shall bear the cost of all tests.

Clause 8:

The work (whether fully constructed or not) and all materials, machines, tools and plant, scaffolding,

temporary buildings and other things connected therewith, shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Engineer- in -charge, and a certificate from him, to the effect, obtained.

Clause 9: Death of Contractor

Without prejudice to any of the rights or remedies under the contract, if the Contractor dies the legal heirs of the Contractor or the Chief Engineer or duly authorised Engineer shall have the option of terminating the contract without any compensation.

Clause 10 : Force Majeure

Neither party shall be liable to each other, for any loss or damage, occasioned by or arising out of acts of God such as-unprecedented floods, volcanic eruptions, earthquake of other invasion of nature and other acts.

Clause 11: General Discrepancies and errors:

In case of percentage rate tenders, if there is any typographical or clerical error in the rates shown by the department in the "G" Schedule. the rates as given in the basic Schedule of Rates of the Department for the area shall be taken as correct.

Clause 12 : Post payment Audit & Technical Examination:

The Government shall have right to provide a system of per-check of Contractor's bill by a specified Organization, and payment by an Engineer or an Accounts Officer/ Sr. Accounts Officer/ Chief Accounts Officer/ Financial Advisor, as the Government may in its absolute discretion prescribe. Any over-payments/ excess payment detected, as a result of such per-check post-check of Contractor's bill, can be recovered from the contractor's bills in the manner, herein before provided and the Contractor will refund such over/ excess payments.

Clause 13 : Check Measurements:

The department reserves to itself, the right to prescribe a scale of check measurement of work in general, or specific scale for specific works of by other special orders (about which the decision on the department shall be final) Checking of measurement by superior officer shall supersede measurements by the subordinate officer and the former will become the basis of the payment. Any over/excess payment detected, as a result of such check measurement or otherwise at any stage up to the date of completion and the defect removal period specified else-where in this contract, shall be recoverable from the Contractor, as any other dues payable to the Government.

Clause 14: Check Measurements:

The Contractor in course of the work should understand that all materials e.g. stone, bricks, steel and other materials obtainable in the work by dismantling etc. will be considered as the property of the Government and will be disposed off to the best advantage on the Government. As per direction of the Engineer-in-Charge.

Clause 15: Recovery from Contractors:

Whenever any claim against the Contractor for the payment of a sum of money arises out of or under the contract, the Department shall be entitled to recover such sum by appropriation in part or whole of the Performance Guarantee and / or Security Deposit. Security Deposit at the time of enlistment of the Contractor. In the event of the security being insufficient, or if no security has been taken, thereafter, may become due to the Contractor, under this or any other contract with the Governor of Rajasthan. Should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable the Contractor shall pay to the Department on demand the balance remaining dues.

The department shall, further, have the right to affect such recoveries under Public Demands Recovery Act.

Clause 16: Jurisdiction of Court:

In the event of any dispute arising between the parties hereto, in respect or any of the matters comprised in this agreement, the same shall be settled by a competent court having jurisdiction over the place, where agreement is executed any by no other court, after completion of proceedings under Clause 23 of this contract.